पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में दावा; पिछले 4 वर्षों से शिक्षा को किया जा रहा साम्प्रदायिक और कैंपस हो रहे हैं आपराधिक

रिपोर्ट में बताया गया है कि हिन्दूवादी ताकतों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के वातावरण को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। उत्तर पूर्व और कश्मीर के छात्रों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि समाज में बढती साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ है.....

जनज्वार, दिल्ली। 'भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों की घेराबंदी' शीर्षक से शैक्षणिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रपट 7 मई 2019 को दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब के डिप्टी स्पीकर हाल में जारी की गई। दिल्ली के अलावा रपट देश के कई राज्यों में भी 7 मई को जारी की गई।

यह रपट देश की शैक्षणिक संस्थाओं की संकटपूर्ण स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। छात्रों को हाशिये पर ढकेलने, बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में यह बहुत अधिक प्रासंगिक है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे लगातार हमलों के चलते सिकुड़ते लोकतांत्रिक दायरों, छात्रसंघों, शिक्षक संगठनों, नागरिक संगठनों ,सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2016 में पीपुल्स कमिशन ऑन श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस इन इंडिया (पीसीएसडीएस) गठित कर भारत में सिकुड़ते लोकतंत्र के दायरे पर जन आयोग (पीसीएसडीएस) 11 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2018 के बीच, भारत में शैक्षिक संस्थानों पर हमलों पर पहला पीपुल्स ट्रिब्यूनल का आयोजन किया। इसमें देश के 17 राज्यों के 50 संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लगभग 130 छात्रों तथा संकायों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये, 49 ने मौखिक गवाहियां दीं।

ज्यूरी पैनल में पूर्व न्यायमूर्ति होसबेट सुरेश, पूर्व न्यायमूर्ति बीजी कोलसे पाटिल, प्रो. अमित भादुड़ी, डॉ उमा चक्रवर्ती, प्रो टीकेओमेन, प्रो वासंती देवी, प्रो घनश्याम शाह, प्रो मेहर इंजीनियर, प्रो.कल्पना कन्नबीरन और सुश्री पामेला फिलिप जैसी विख्यात हस्तियां शामिल थी।

ज्यूरी पैनल के सामने 17 विशेषज्ञों ने शिक्षा में निजीकरण और वैश्वीकरण से पड़ने वाले प्रभाव, इतिहास और पाठ्यक्रम के विकृतिकरण, शिक्षा का भगवाकरण और विद्रूपण, विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र संघों के चुनाव, विरोध का अपराधीकरण, जाति,लिंग, क्षेत्र, धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव आदि विषयों पर विचार व्यक्त किये। ट्रिब्यूनल के अंतिम दिन शपथपत्रों एवं मौखिक गवाहियों के आधार पर जूरी पैनल द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी की गई।

जूरी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि भारत में उच्च शिक्षा के विचार पर ही संस्थागत-सुनियोजित हमला किया जा रहा है। ज्यूरी के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दशक में संकट लगातार गहराता रहा है, जो विशेषतौर पर पिछले 4 वर्षों में गंभीर हो गया है। यह सुनियोजित तौर पर किया जा रहा है क्योंकि शिक्षित नागरिक ही सत्ताधीशों से सवाल पूछ सकते हैं, जो लोकतंत्र के गहरीकरण और विस्तारण के लिये आवश्यक है।

यह संकट केवल शिक्षा का ही नहीं वरन पूरे समाज का है। 'शपथ पत्र और गवाहियाँ' के दौरान शिक्षा के निजीकरण और वैश्वीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा बजट में कमी किए जाने, शुल्क बढ़ोतरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता में कमी के परिणामस्वरूप इन समुदायों के हाशिये पर पहुँच जाना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों, छात्रवृत्ति में देरी और उसे कम किया जाना, प्रवेश प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की खस्ता स्थिति आदि मुद्दों को रेखांकित किया गया।

गवाहियों के दौरान यह खुलासा हुआ कि हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा सुनियोजित तौर पर पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है। इसके चलते संवैधानिक मूल्यों–धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और लोकतान्त्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है। यह भी स्पष्ट हुआ कि विश्वविद्यालयों कि स्वायतता को सत्ताधीशों द्वारा अपने लोगों को बैठाकर सवाल पूछने वाले तथा विरोध कि आवाजों को कुचला जा रहा है।

विभिन्न छात्रों ओर संकायों ने बताया कि छात्रसंघ के चुनावों के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संघ से जुड़े छात्र संघों के पक्ष में वोटिंग के लिए दबाव डाला जाता है। चुने हुए छात्र संघों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है तथा विरोध का दमन व अपराधीकरण किया जा रहा है। एफटीआईआई, जेएनयू, एचसीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बीबीएयू, पंजाब विश्वविद्यालय, टीआईएसएस, गौहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों, संकायों ने बताया कि उन्हें किस तरह से सुनियोजित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आपराधिक तौर तरीके अपनाकर विरोध को खत्म करने कि कोशिश की जा रही है। राष्ट्रद्रोह, आगजनी, दंगे फैलाने दंगों से जुड़े आरोप लगा कर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति—जनजाति विरोधी नीतियों को अपनाये जाने के चलते इन समुदायों के छात्र असुरक्षित हो गए हैं तथा उन्हें हाशिये पर डाल दिया गया है। उनके साथ भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में यौन प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थायें कानूनी और नीतिगत प्रावधानों को परिसरों में लागू नहीं कर रही हैं। विशेष तौर पर पूर्वोत्तर और कश्मीरी छात्रों को प्रताड़ित किये जाने, उनके साथ भेदभाव किये जाने तथा हिन्दूवादी ताकतों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के वातावरण को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। उत्तर पूर्व और कश्मीर के छात्रों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि समाज में बढती साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ है।

जूरी ने शैक्षणिक संस्थाओं में चौतरफा संकटों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त हुए कहा कि यदि इस तरह तुरंत ध्यान नहीं किया गया तो भारत की उच्च शिक्षा को ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिये गंभीर खतरे पैदा हो जायेंगे। पीसीएसडीएस के संयोजक अनिल चौधरी ने मीडिया से पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने की अपील की ताकि उच्च शिक्षा में उभरते मुद्दे और चिंताएँ अधिकतम लोगों तक पहुँच सके और लोग सच्चाई से वाकिफ हो सकें।

ये जो बच्चे 95 और 99.9 प्रतिशत अंक पा रहे हैं.....

कविता कृष्णपल्लवी

इनके माँ-बाप अपना 56 इंची सीना टोले-मोहल्ले और फेसबुक पर दिखा रहे हैं, मुआफ़ करें, इससे मुझे कोई खुशी या उत्साह अनुभव नहीं हो पाता। ऐसे तमाम अभिभावक अपने बच्चों को हैसियत, पैसे और सुरक्षा के लिए जारी भेड़ियाधसान, कुत्ता-दौड़ और चूहा-दौड़ के कुशल प्रतिस्पर्द्धी बना रहे हैं और जाहिर है कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वे पूरी तरह आश्वस्त हो लेना चाहते हैं! पर इन बच्चों के सभी शुभेच्छु न तो समाज के भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं और न ही ये बच्चे , अपवादों को छोड़ दें तो, कभी इतने संवेदनशील बन पाते हैं कि समाज के उपेक्षितों-लांछितों-दमितों-उत्पीड़ितों की तरफ उनका ध्यान जाए। इन बच्चों को बस एकमात्र यह लक्ष्य दिया जाता है कि वे डाक्टर-इंजीनियर बनकर खूब धन कमायें, मोटे-मोटे पैकेज लेकर आई टी सेक्टर में जाएँ या कलक्टर-एस.पी. बनकर अपने हक की आवाज़ उठाते लोगों पर लाठियों-गोलियों की बौछार करें।

ये बच्चे और इनके माँ-बाप कभी भी पीछे छूट गए बच्चों के बारे में नहीं सोचते और यह मानकर चलते हैं कि जो मेधावी और परिश्रमी थे वे आगे निकल गए और अयोग्य और आलसी पीछे छूट गए। उनके भेजे में यह बात तक नहीं आती कि हर बच्चे में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता होती है, जो उनकी पारिवारिक स्थिति और इस शिक्षा-व्यवस्था के कारण उभरकर सामने आ ही नहीं पाती। उनकी खोंपड़ी में यह बात घुस ही नहीं पाती कि इस शिक्षा-व्यवस्था का ढाँचा गढ़ा ही इसतरह गया है कि उत्पादन और विनिमय और राज-काज के पूरे तंत्र को चलाने के लिए जितने नौकरशाह, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, सेनाधिकारी आदि चाहिए, उतने को चुन लेने के बाद शेष आबादी को बौद्धिक और शारीरिक उजरती गुलामी करने वाली भीड़ में धकेल दिया जाए और उनके दिमाग में यह बात कूट-कूट कर बैठा दिया जाए कि वे इसी लायक थे। शिक्षा इसी मामले में 'आयडियोलोजिकल स्टेट-आपरेटस' है, जिसके द्वारा शासक वर्ग अपनी हेजेमनी स्थापित करता है। यह भी अनायास नहीं है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी की चूहा-दौड़ में 90-95 प्रतिशत वही आगे निकल पाते हैं जो समाज के 'विशेषाधिकार-प्राप्त उपभोक्ता समाज' के भीतर से, यानी खाते-पीते परिवारों से आते हैं ! ऐसा इंतज़ाम किया ही इसलिए गया है कि सामाजिक संस्तरों के स्थापित पद-सोपान-क्रम में ज्यादा उथल-पुथल न हो। इसके जो अपवाद होते हैं, उनके उदाहरण दे-देकर अच्छे अंक पाने वाले और ऊँचे पदों-ओहदों पर पहुँचने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि 'फलां को देखो, अपनी मेहनत और काबिलियत से कहाँ पहुँच गया!' यानी जो नहीं पहुँच सके वे हैं ही काहिल और मूर्ख ! यह 'सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट' का बर्बर तर्क है, जहाँ सारी योग्यता हैसियत और आर्थिक ताक़त से तय होती है।

प्रतिस्पर्द्धा पूँजीवाद की मूल चालक शक्ति होती है ! इसलिए पूँजीवादी समाज के हर नागरिक के दिलो-दिमाग में यह तर्क बैठाना होता है कि 'भई, तुम प्रतिस्पर्द्धा में पीछे छूट गए तो तुम इसी लायक हो, और अब अपनी इस स्थिति को सर झुकाकर स्वीकार करो।' सारी योग्यता इस बात से तय होती है कि तुम इस खूनी-बर्बर व्यवस्था के नट-बोल्ट बनने के लिए कितने अनुकूल हो।

मैंने सैकड़ों कैरियरवादी छात्रों को, सिविल सेवा की, विदेश जाने की या ऐसी ही किसी चीज़ की तैयारी करने वाले युवाओं को देखा है। अपवादों को छोड़ दें तो इनकी बड़ी संख्या राजनीतिक-सामाजिक ज्ञान के मामले में निहायत कूपमंडूक तो होती ही है, ये प्राय: रुग्णता की हद तक स्वार्थी, व्यक्तिवादी और कमीने होते हैं। आपको कभी पीले-बीमार चेहरों वाले इन लोगों के अंतर्जगत में झाँकने का मौक़ा मिले तो आप पायेंगे कि ये आत्मिक रूप से दिवालिया और नैतिक रूप से निहायत गिरे हुए लोग होते हैं। व्यवस्था जितनी अधिक रुग्ण, संकटग्रस्त और आततायी होती जाती है, उसे ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और तब ऐसे लोग भारी तादाद में बाज़ार में उपलब्ध भी हो जाते हैं।

मैं जब बहुतेरे वाम-प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को देखती हूँ कि वे अपने बेटे-बेटी-नाती-पोते आदि-आदि के 95 और 99 प्रतिशत अंक पाने की खुशी सोशल मीडिया पर भी डागा-बाजा बजाकर करते हैं तो मुझे क्षोभ होता है। वे अपनी निजी खुशी के साथ इस अन्यायी शिक्षा-व्यवस्था को एक तमगा भी दे रहे होते हैं और प्रकारांतर से उन लोगों की खिल्ली भी उड़ा रहे होते हैं जो अपनी सामाजिक-पारिवारिक स्थिति और इस शिक्षा-व्यवस्था द्वारा निर्धारित योग्यता के घनघोर अन्यायपूर्ण और अवैज्ञानिक पैमाने के कारण पीछे छूट गए। यही वामपंथ को कलंकित करने वाले वे भारतीय फ्रॉड हैं जो भगतसिंह पर लेख और किताबें लिखते हैं, लेक्चर देते हैं और अगर भगतसिंह पड़ोस के बजाय उनके घर में पैदा हो जाए तो शोक में डूब जाते हैं ! ज़रा नज़र घुमाकर अपने आस-पास के बुज़ुर्ग वामपंथी बुद्धिजीवियों को देखिये। उनमें से 80 प्रतिशत के बेटे-बेटियाँ विदेशों में सेटल हैं (जहाँ वे अपनी छुट्टियाँ बिताने जाया करते हैं) या फिर देश में ही उच्चपदस्थ नौकरशाह हैं, आई.टी. सेक्टर में हैं, प्रोफ़ेसर-डाक्टर-इंजीनियर हैं ! बात ठीक है कि सभी वामपंथियों के बच्चे वामपंथी बन जाएँ, यह ज़रूरी नहीं। यह बलात नहीं किया जा सकता।

मगर यह भी इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता कि 2-3 प्रतिशत वामपंथियों के बच्चे भी वामपंथी नहीं बन पाते। मैंने खुद ऐसे सैकड़ों वाम बुद्धिजीवी देखे हैं जिनका माथा मार्क्सवाद के " ज्ञान" से एक-एक कुंतल का हो गया है, लेकिन जो अपने बेटे-बेटियों को सिविल सर्विस, पी.एम.टी., इंजीनियरिंग, नेट आदि की तैयारी कराने पर धोती खूँटकर पिले रहते हैं और किसी भी प्रकार की सामाजिक सक्रियता और अपने विचारों से पूरी तरह काटकर रखते हैं। ऐसे वामपंथियों पर गरीब मेहनतक़श अवाम भला क्यों भरोसा करे ?

टॉपर्स के नाम एक बैक-बैंचर का खत

सौ फीसदी से सिर्फ एक अंक कम लाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों और उनके अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। अच्छा किया आपने! यह आपकी मेहनत, लगन, त्याग और समर्पण का नतीजा है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। कैसे हो सकती है, यह मामला तो बधाइयों वाला है। शिकायत तो तब होती है जब यही बच्चा आईएएस में भी टॉपर जैसा कुछ बनता है और कहता है कि मैं देश की सेवा करूँगा। फिर वह देश की सेवा क्या और कैसे करता है, यह आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी। अपना मुल्क इतने बरस से टॉपर्स से सेवा ही करवा रहा है। इतनी सेवा करवा रहा है कि मुल्क की देह में हड्डियां उभर आई हैं। टॉपर्स अलबत्ता नियमित जिम जाने के बाद भी मुटाए चले जा रहे हैं।

आप मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा न मानें। मैं खुद एक बैक-बैंचर हूँ और आप लोगों की सफलता से जल रहा हूँ। कुंठित हूँ। आपको वह मिल रहा है, जिसके आप हकदार हैं। आप अपनी भाषा में इसे शायद 'डिजर्व' करना कहते हैं। हम वह सब भोग रहे हैं, जो धतकरम हमने किए। पर ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक है।

अभी पिछले ही साल इंग्लिश का पर्चा ऐन होली के अगले दिन पड़ गया था। जब हम होली खेल रहे थे तो आप 'अ होली फेस्टिवल ऑफ इंडिया' निबन्ध का रट्टा मार रहे थे। ऐसा अपन लोगों के साथ हमेशा होता रहा। हम आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते थे और आप आम के पेड़ पर निबंध लिखते थे। इसलिए पिछली बार जब अपन वेकेशनल टूर पर एक अभ्यारण्य गए थे तो आपने कटहल के पेड़ को देखकर कहा था, 'वाऊ, व्हाट ए ब्यूटीफुल मैंगो ट्री!' आपके एक जोड़ीदार ने बताया था कि दूध बोतल से निकलता है। उन्होंने कभी गाय या भैंस को दुहाते हुए नहीं देखा। और एक बार जब मैंने आपको अनानास का एक टुकड़ा खाने को दिया तो आपने कहा था कि, 'वाऊ, इसका फ्लेवर तो बिल्कुल पाइनएप्पल आइसक्रीम जैसा है।' पर कोई बात नहीं। आप अपनी अज्ञानता को भी ग्लोरीफाई कर सकते हैं। मैम भी कह रही थीं कि टॉपर्स को यह सब देख-सुन पाने की फुर्सत कहाँ मिलती है।

माफ कीजियेगा, मैं आपकी कमी नहीं निकाल रहा हूँ। थोड़ी जलन है तो गुबार तो निकल ही जाता है। और वैसे भी शिकायत आपसे तो बिल्कुल नहीं है। शिकायत उन अभिभावकों से है, जिनके बच्चे बेचारे आप जैसे मर-खप कर भी सिर्फ 90 परसेंट ला सके। न उनने पतंग उड़ाई, न कंचे खेले, न स्कूल से भागकर सिनेमा देखा, न क्लास में पीछे बैठकर दोस्तों की पीठ की ओर चाक उछाली और इसके बाद भी माँ-बाप के ताने सुनने को मिल रहे हैं। अब दौड़ है तो कोई अव्वल तभी आ सकता है, जब कुछ लोग पीछे हों। इसीलिए अपन कोशिश भी नहीं करते। कोशिश करेंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि 'सब कुत्ते काशी चले जायेंगे तो पत्तल कौन चाटेगा ?'

तो ऐसा है कि पत्तल चाटने वाली जिम्मेदारी अपनी है। यह स्वछता अभियान का एक हिस्सा है और इसलिए यह भी एक किस्म की देश सेवा है। अब देश सेवा की बात निकल ही पड़ी है तो कांफीडेंशली आपसे कहना चाहता हूँ कि यह चोचला आप लोगों को नहीं सुहाता। आप तो बस अपने करियर, पगार, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगले और होने वाले अपने बच्चों को फॉरेन में सैटल करने की तैयारी के बारे में सोचें। असली देशसेवा तो बैक बेंचर ही करता है जो रोजी-रोटी के मारे आर्मी, पुलिस, होमगार्ड, टीचर, फटीचर से लेकर हर कहीं खटने वाली चाकरी-मजूरी करता है। एसी चैंबर में बैठकर सिर्फ अपनी सेवा होती है।

कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया ? कहा-सुना माफ करना!

- दिनेश चौधरी